भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 236
दिनांक 10 अगस्त, 2026

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा

236 **डॉ. रामराव सखाराम वडकुतेः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम एशिया में हाल ही के भू-राजनीतिक व्यवधानों के दौरान भारत की पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कच्चे तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में व्यवधानों से निपटने हेतु भारत की तैयारी की कोई समीक्षा की है;

(ग) आयात के स्रोतों में विविधता लाने तथा रणनीतिक भंडार को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने हेतु किसी दीर्घकालिक नीतिगत परिवर्तन का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा' के बारे में संसद सदस्य डॉ. रामराव सखाराम वडकुते द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 236 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) पश्चिम एशिया में हाल की भू-राजनीतिक स्थिति के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से समुद्री यातायात बाधित हो गया, जो भारत के लगभग 45% कच्चे तेल आयात, 90% एलपीजी आयात और 55% एलएनजी आयात से जुड़ा मार्ग है। भारत में 1 लाख से अधिक खुदरा बिक्री केंद्रों और 33 करोड़ एलपीजी सक्रिय घरेलू उपभोक्ताओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क देखते हुए, इस व्यवधान ने देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए अभूतपूर्व तनाव-परीक्षण प्रस्तुत किया है। इस व्यवधान की व्यापकता के बावजूद, सरकार ने आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण, लचीली अधिप्राप्ति, इनवेंट्री में वृद्धि, बुनियादी ढांचे की तैयारी, घरेलू उत्पादन के अनुकूलन आदि उपायों पर आधारित एक व्यापक, समग्र सरकारी प्रतिक्रिया के माध्यम से पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। परिणामस्वरूप, देश में कोई भी खुदरा ईंधन बिक्री केन्द्र खाली नहीं हुआ और घरेलू एलपीजी, पीएनजी और परिवहन सीएनजी की आपूर्ति मांग के 100% पर बनी रही। सरकार ने देश के नागरिकों पर अंतरराष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए भी सुनियोजित उपाय अपनाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की कीमतों में काफी वृद्धि के बावजूद, दक्षिण एशियाई क्षेत्र और उससे बाहर के अन्य देशों की तुलना में घरेलू ईंधन की कीमतों में केवल सीमित वृद्धि देखी गई, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को राहत मिली।

देश	पेट्रोल (रु./लीटर)			डीजल (रु./लीटर)		
	जून '22	जून '26	(%)	जून '22	जून '26	(%)
पाकिस्तान	92.64	129.48	39.77%	79.98	130.51	63.18%
श्रीलंका	90.43	123.59	36.66%	86.13	115.90	34.57%
नेपाल	113.99	137.19	20.36%	103.22	142.25	37.81%
बांग्लादेश	76.97	109.82	42.69%	71.60	90.21	26.00%
इटली	166.85	206.27	23.63%	161.38	215.58	33.59%
जर्मनी	163.18	209.60	28.45%	167.70	197.25	17.62%
फ्रांस	174.18	217.77	25.02%	171.06	214.73	25.53%
भारत (दिल्ली)	96.72	102.12	5.58%	89.62	95.20	6.23%

ऊर्जा सुरक्षा संरचना के अभिन्न अंग के रूप में सरकार ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधानों से निपटने के लिए देश की तैयारियों की निरंतर समीक्षा करती है, और हालिया संकट के दौरान इस समीक्षा प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और कोयला एवं खान मंत्रालय के प्रतिनिधियों की अधिकार प्राप्त सचिवों के एक समूह का गठन संकट की अवधि के दौरान किया गया जिसकी कई बैठकें हुईं, जिससे वास्तविक समय में मुद्दों का समाधान किया गया और सरकार की समन्वित एवं सुसंगत प्रतिक्रिया सुनिश्चित की गई। फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल इनपुट पर निर्भर अन्य आवश्यक क्षेत्रों सहित डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक आपूर्ति की निरंतरता की समीक्षा और सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया था। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को एलपीजी से पाइप्ड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की समीक्षा और उसमें तेजी लाने के लिए नगर गैस वितरण कार्य-बलों का गठन किया गया था। औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच आवश्यक आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध प्राकृतिक गैस के आवंटन और समीक्षा के लिए एक क्षेत्र-वार प्राथमिकता ढांचा भी स्थापित किया गया था। इन तंत्रों ने सरकार को पश्चिम एशिया संकट के दौरान लगातार कमजोरियों की पहचान करने और अपनी प्रतिक्रिया को समायोजित करने में सक्षम बनाया।

पिछले एक दशक में आयात स्रोतों के संरचनात्मक विविधीकरण को आगे बढ़ाया है, जो हालिया व्यवधान के दौरान निर्णायक साबित हुआ।

पिछले एक दशक में कच्चे तेल के लिए भारत की स्रोत भौगोलिक स्थिति 27 से बढ़कर 41 आपूर्तिकर्ता देशों तक पहुंच गई है। खाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक स्रोतों से आपूर्ति बाधित होने पर, भारतीय तेल कंपनियों ने यूरेशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी उत्पादकों से अन्य आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्ति में तेजी से वृद्धि की।

एलपीजी आपूर्ति करने वाले देशों की संख्या 10 से बढ़कर 15 हो गई है और अब एलपीजी की आपूर्ति दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कई विविध आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। इस कार्यनीति के तहत, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) ने अमेरिका से आयातित लगभग 22 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) एलपीजी के आयात के लिए अनुबंध किए हैं, जो देश की कुल एलपीजी आयात आवश्यकता का लगभग 10% है। संकट के दौरान खाड़ी क्षेत्र से एलपीजी आयात में लगभग 90% व्यवधान के बाद, इन देशों से वैकल्पिक आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित की गई।

एलएनजी की आपूर्ति 6 देशों से बढ़कर 15 देशों तक हो गई है। संकट के दौरान, खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति में आई कमी की भरपाई के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तीन स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता वाले कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) संयंत्र स्थापित किए हैं। सरकार ने ओडिशा और कर्नाटक में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता वाले दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार संयंत्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को कर्नाटक में 1.75 एमएमटी क्षमता वाला एक कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार संयंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, पिछले दशक में भारत की घरेलू शोधन क्षमता लगभग 215 एमएमटीपीए से बढ़कर लगभग 267 एमएमटीपीए हो गई है, और संकट के दौरान भी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां अपनी निर्धारित क्षमता के 100-105% पर काम कर रही थीं। एलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल की क्षमता दोगुनी हो गई है, जो चार से बढ़कर आठ टर्मिनल हो गई है, जिनकी क्षमता लगभग 52.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है। नगर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार 309 भौगोलिक क्षेत्रों तक हो गया है, जिसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश का पूरा भूभाग शामिल है। पिछले दशक में हुए इस बुनियादी ढांचे के विस्तार ने पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए भू-राजनीतिक व्यवधानों के दौरान आपूर्ति की उपलब्धता को सुचारू बनाने में मदद की।

सरकार ने कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए बहुआयामी कार्यनीति भी अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

- देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन करना, जिससे अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़े और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ जा सके,
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना,
- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना,
- किफायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (सतत) पहल शुरू करके ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देना।

सरकार ने भारत की अपतटीय जलकार्बन क्षमता को उजागर करने और तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 84,084 करोड़ रुपए के प्रथम चरण के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना तीन प्रमुख घटकों पर आधारित है- भूकंपीय डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या, अवसंरचना-आधारित उत्पादन के साथ अपतटीय अन्वेषण में तेजी लाना और निगरानी एवं सहायक गतिविधियाँ।

सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, गोबर्धन को मंजूरी दे दी है, जो देश के प्रचुर मात्रा में मौजूद कृषि अवशेष, गोबर, प्रेस मड, नगरपालिका के जैविक अपशिष्ट और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करेगा।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में जैव ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादित जैव ईंधन वैश्विक कच्चे तेल की अस्थिरता से अप्रभावित रहते हैं और दीर्घकालिक रूप से भारत के ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण जैव ईंधन पहलों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, एटीएफ के साथ एसएएफ का मिश्रण और डीजल के साथ जैव-डीजल का मिश्रण शामिल हैं। सरकार ने देश में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोबर्धन कार्यक्रम के तहत 23,731 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

*****